

मूक पात्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 01 बेमेतरा, गुरुवार 13 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

सेवा की भावना पर दिया जोर

पीएम मोदी ने युवाओं को भारत की वर्तमान ताकत बताया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत के युवाओं को न केवल देश का भविष्य, बल्कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने युवाओं की संवेदनशीलता, सेवा की भावना और क्षमताओं पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हमारे युवा साथी न केवल देश का भविष्य हैं, बल्कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, सेवा की भावना और क्षमता के माध्यम से दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया: चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्,



प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति। इस श्लोक का संदेश है कि जो व्यक्ति दृष्टि, मन, वाणी और कर्म—इन चार माध्यमों से लोगों का दिल जीतता है या उनकी सेवा करता है, उसे बदले में समाज

से स्नेह और सद्भावना मिलती है।

प्रधानमंत्री के संदेश ने युवाओं को भारत के वर्तमान और भविष्य के विकास के केंद्र में रखा, साथ ही सहानुभूति, सेवा और व्यक्तिगत क्षमता जैसे मूल्यों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर देश को पहचान दिलाने में युवा भारतीयों के योगदान को भी रेखांकित किया। मोदी ने राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर बार-बार जोर दिया है, विशेष रूप से नवाचार , उद्यमिता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी और जन-सेवा जैसे क्षेत्रों में। सरकार ने देश की युवा आबादी को 'विकसित भारत' के अपने व्यापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास

मोदी ने की 'विश्व हाथी दिवस' पर गजराज के संरक्षण में जुटे लोगों की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विश्व हाथी दिवस' पर बुधवार को हाथियों को भारत की पारिस्थितिकी विरासत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए उनके संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों की सराहना की। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा यह खुशी की बात है कि भारत में दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं। देश में 33 हाथी अभयारण्य हैं, जो हाथियों को आवास उपलब्ध कराने और उनके दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भी किया है।क्षमता के साथ-साथ संवेदनशीलता और सेवा की भावना को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री के इस नवीनतम संदेश ने यह रेखांकित करने का प्रयास किया कि युवा भारतीयों का योगदान केवल आर्थिक और पेशेवर

उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है। संदेश के अनुसार, समाज के साथ उनका जुड़ाव, जन-सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और व्यापक समुदाय में योगदान देने की उनकी इच्छा देश की प्रगति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित

नयी दिल्ली। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 को बुधवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया जिससे इस पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

द्रमुक के तिरुचि शिवा ने विधेयक के कुछ प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव दिये थे जिन्हें सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने विधेयक को सहकारिता मंत्री अमित शाह के स्थान पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले द्वारा पेश किये जाने का विरोध किया। इस मुद्दे पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा नेता सदन जगत प्रकाश नड्ड के बीच



तकरार भी हुई। इसके बाद कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। विधेयक पर हुई चर्चा और उस पर मोहोले के संक्षिप्त जवाब के बाद सदन ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। मोहोले ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया है।

चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ : अमित शाह



नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं। वह अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।



माकपा सदस्य के आरोप पर राज्यसभा में पक्ष-विपक्ष में तकरार,कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
राज्यसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जॉन ब्रिटान ने सत्ता पक्ष की एक महिला सदस्य पर उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जिसके कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोक झोंक हुई और सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में अलग-अलग मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण मानसून सत्र में अब तक एक भी दिन शुन्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पायी है। इस सत्र का यह अंतिम सप्ताह है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र का गुरुवार यानी कल अंतिम दिन है। सदन में अब तक ज्यादातर कामकाज विपक्ष के हंगामे या बहिर्गमन के बीच ही हुआ है।

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। शाह ने कहा, आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

अमित शाह का भाषण नहीं, हमें जवाब चाहिए : राहुल

नयी दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग कर रहे हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए।

गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब



अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र

की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'सच ये है कि अमित शाह की इमेज

का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।' गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, 'अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।'

उन्होंने कहा कि जब देश के छात्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शाह से नहीं डर रहे हैं तो मीडिया को भी उनसे डरना नहीं चाहिए।

होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कब्जा : ट्रंप

मैरीलैंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर बरोसा नहीं करते हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। ट्रंप ने यहां संवाददाताओं से कहा, मुझे ईरान पर बरोसा नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे ईरान पर बरोसा है? मुझे ईरान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ईरानी पक्ष ने हमेशा झूठ बोला है। ट्रंप ने होर्मुज पर नियंत्रण का दावा करते हुए कहा कि अगर ईरान स्थिति बदलने की कोशिश करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य पर हमारा पूरा नियंत्रण है। उनका इसपर कोई

नियंत्रण नहीं। हम उसे चला रहे हैं। अगर ईरान कभी कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे 'उड़ा दिया' जायेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय मजबूत स्थिति में है और दावा किया कि ईरान ने क्षेत्र में अपना पिछला प्रभाव खो दिया है।

उन्होंने कहा, अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे सामने एक ऐसा देश है जो 50 वर्षों से मध्य पूर्व में दबाव बना हुआ था... अब वह पश्चिम एशिया का दबाव नहीं रहा। गौरतलब है कि फरवरी के अंत में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद क्षेत्र में जारी तनाव के बीच उनकी इस तरह की टिप्पणियां आई हैं।

कश्मीर में तिरंगा आन- बान और शान के साथ लहराते हुए देखना सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय: नवीन



नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि कश्मीर में तिरंगा आन- बान और शान के साथ लहराता हुआ नजर आ रहा है जो सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है।

नवीन कर्तव्य पथ पर

आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कहा कि 2011 में जब श्रीनगर के लाल चौक पर देश का तिरंगा लहराने पर सवाल उठते थे, तो देश के करोड़ों युवाओं के दिल में दर्द होता था।

हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री निवास में साकार हुई छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कृषि परंपरा और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी

पारंपरिक वेशभूषा में पिंग ऑटो से कार्यक्रम स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह
रायपुर/प्रेरणाश्रोत। छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सौंधी महक, खेत-खलिहानों की परंपराएं, लोकगीतों की स्वर लहरियां, मांदर की थाप, गेड़ी का उल्लास और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू - प्रदेश के प्रथम लोक पर्व हरेली तिहार पर आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी में बदल गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधि-विधान से भगवान शिव, गौमाता और कृषि औजारों की पूजा-अर्चना कर प्रदेश में अच्छी वर्षा, भरपूर फसल, किसानों की समृद्धि और सभी परिवारों की सुख-खुशहाली की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारी, किसान और बड़ी संख्या में नागरिक इस उत्सव के साक्षी बने।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर किसान भाई-बहनों को हरेली तिहार की गाड़ा-गाड़ा बधाई देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन के बीच आत्मीय रिश्ते का उत्सव



है। यह पर्व हमें अपनी धरती, पशुधन, कृषि उपकरणों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और प्रदेश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती-किसानी से जुड़ी है। किसान की समृद्धि ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मजबूत आधार है।

पारंपरिक वेशभूषा में पिंग ऑटो से पहुंचे मुख्यमंत्री

हरेली के उत्सव में मुख्यमंत्री साय पूरी तरह छत्तीसगढ़ी रंग में रंगे नजर आए। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर वे विधानसभा अध्यक्ष डॉ.

रमन सिंह के साथ महिला ऑटो चालक संगीता यादव के पिंग ऑटो में मुख्यमंत्री निवास परिसर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस अनूठे अंदाज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उत्सव के माहौल में आत्मीयता का रंग घोल दिया। कार्यक्रम का शुरुआत गौरी-गणेश एवं नवग्रह पूजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग का अभिषेक किया और नांगर, रापा, कुदाल, फवड़ा सहित खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि औजारों की विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नमन किया।



मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हरेली के समय तक खेती के अनेक प्रमुख कार्य पूरे हो चुके होते हैं और किसान प्रकृति एवं अपने कृषि साधनों की पूजा कर अच्छे कृषि वर्ष की कामना करते हैं। यह परंपरा हमारे पुरखों की प्रकृति के प्रति गहरी समझ और सम्मान को दर्शाती है।

गौमाता को खिलाई पारंपरिक लोंदी, पशुधन संरक्षण का दिया संदेश

मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्मित गौशाला पहुंचकर गौमाता की आरती और पूजा-अर्चना की। उन्होंने गाय और बछड़े

को हरा चारा, चना-गुड़ तथा पारंपरिक 'लोंदी' खिलाई। हरेली पर पशुधन को लोंदी खिलाने की लोक परंपरा पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और रोगों से बचाव की कामना से जुड़ी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में पशुधन परिवार और कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है।

हमारी लोक संस्कृति हमें पशुओं के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और संरक्षण की सीख देती है। आधुनिकता के साथ अपनी ऐसी उपयोगी और प्रकृति-सम्मत परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।



किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुए किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को खेती के लिए सहज रूप से पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता खोला। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने सहकारी कृषि ऋण की ब्याज दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते हुए अंततः शून्य प्रतिशत तक पहुंचाया।



संपादकीय

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अमेरिकी अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी पर 5000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म में बदलाव करने के लिए कहा है।बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर अमेरिका की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट

कंपनी मेटा पर करीब 5,390 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने पिछले साल 60 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में जुर्माने की रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण अदालत का यह आदेश है कि कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने प्लैटफॉर्म में बदलाव करने होंगे।नाकाम रही कंपनी। न्यू मैक्सिको की अदालत ने माना कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इन प्लैटफॉर्म

को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन मेट किया गया है कि बच्चों को इसकी लत लग जाए। नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने में भी कंपनी नाकाम रही है। यूएस में लगा जुर्माना-की रकम का एक हिस्सा पीड़ितों पर खर्च करने का आदेश दिया है, जो बताता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकतीं। उनकी वजह से समाज में जो परेशानी शुरू हुई है, उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी।

किसी सोशल मीडिया कंपनी को पहली बार इस तरह कटघरे में खड़ा होना पड़ा है और मेटा के लिए परेशानी की बात यह है कि अमेरिका के कई और राज्यों में भी इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। इससे पहले मार्च में भी मेटा पर 3500 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा था। गैर-कानूनी कंटेंट-पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि बच्चों को किस हद तक सोशल मीडिया इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए। कई

देशों ने अपने यहां निश्चित उम्र सीमा भी लागू की है। हालांकि इसके साथ जरूरी मुद्दा यह भी है कि सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। भारत में भी मेटा लगातार विवादों में है। पीएम नरेंद्र मोदी के एक विडियो को फेसबुक से हटाए जाने पर उसने माफी मांग ली।यह तकनीकी गलती हो सकती है, पर पेड़ प्रमोशन के जरिये गैर-कानूनी कंटेंट को बढ़ावा देने की बात उसने खुद मानी है। इस साल जुलाई में

केंद्र ने नोटिस भी जारी किया था। बैन उपाय नहीं- अमेरिकी अदालत ने अगले पांच बरसों में मेटा को कई सुरक्षा उपाय अपनाने का आदेश दिया है। इस तरह के कदम बाकी जगहों पर भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया किसी एक देश तक सीमित नहीं रही। हालांकि यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी तरह बैन उपाय नहीं है, जरूरत जवाबदेही और नियंत्रण की है।

अगर भारत-पाक युद्ध हुआ तो क्या भारत के खिलाफ अपनी सेना उतारेंगे तुर्की और सउदी अरब ?

(नीरज कुमार दुबे)

वर्तमान हालात को देखें तो सऊदी को चाहिए सुरक्षा, पाकिस्तान को पैसा और तुर्किये को ताकत, इसलिए तीनों एक साथ आ गये हैं। हालांकि इस गठजोड़ को समझने के लिए तीनों देशों के हितों को अलग-अलग देखना होगा। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। नाटो के भीतर जब अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच भरोसे की दरारें गहरी हो रही हैं, ठीक उसी समय पश्चिम एशिया में एक नया शक्ति-केंद्र खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। मक्का में तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ऐसा रक्षा समझौता किया है, जिसकी सबसे अहम लाइन में साफ कहा गया है कि तीनों में से किसी एक पर हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यही वह बिंदु है, जो इस समझौते को सामान्य सैन्य सहयोग से उठाकर एक संभावित नए क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में बदल देता है। हालांकि इसे अभी आधिकारिक तौर पर ‘सुन्नी नाटो’ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके भीतर उसकी बुनियादी तस्वीर जरूर दिखाई देने लगी है। देखा जाये तो मक्का में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन का एक मंच पर आना अपने आप में बड़ा संदेश है। खास बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया पहले ही ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की आग में झूलस रहा है। सऊदी अरब पर ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के हमलों का खतरा है। पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और तुर्किये पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। यानी तीनों देश एक-दूसरे की जरूरत बन गए हैं।

क्यों हुआ त्रि-पक्षीय समझौता ? – वर्तमान हालात को देखें तो सऊदी को चाहिए सुरक्षा, पाकिस्तान को पैसा और तुर्किये को ताकत, इसलिए तीनों एक साथ आ गये हैं। हालांकि इस गठजोड़ को समझने के लिए तीनों देशों के हितों को अलग-अलग देखना होगा। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। दशकों तक रियाद ने अमेरिकी सुरक्षा छाते पर भरोसा किया। लेकिन अब सऊदी नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि बदलती अमेरिकी नीति में किसी एक बाहरी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ईरान और उसके सहयोगियों की मिसाइल तथा ड्रोन क्षमता ने इस खतरे को और वास्तविक बना दिया है। ऐसे में सऊदी अरब ने अपना सुरक्षा कवच चौड़ा करना शुरू किया है। पाकिस्तान उसके लिए एक विशेष साझेदार है। पाकिस्तानी सेना दशकों से सऊदी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देती रही है और हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिकों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों की मौजूदगी भी बढ़ाई है। वहीं पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल दूसरी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से निवेश और आर्थिक मदद चाहिए, जबकि तुर्किये से रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग चाहिए। बदले में पाकिस्तान अपनी सेना और परमाणु क्षमता को मुस्लिम दुनिया की सुरक्षा में सबसे बड़ा सैन्य योगदान बताकर अपनी भू-राजनीतिक अहमियत बढ़ाना चाहता है। वहीं तुर्किये की बात करें तो एर्दोगन लंबे समय से अपने देश को सिर्फ नाटो का सदस्य नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया की एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्किये के पास अत्याधुनिक ड्रोन, रक्षा उद्योग और बड़ी सैन्य ताकत है। पाकिस्तान के साथ उसका रक्षा सहयोग पहले ही तेजी से बढ़ चुका है।

यह गठबंधन किसके खिलाफ है? – अब सवाल उठता है कि यह गठबंधन किसके खिलाफ है? इस सवाल का जवाब हालांकि तीनों देशों ने नहीं में दिया है। तुर्किये ने साफ कहा है कि समझौता रक्षात्मक है, यह किसी खास देश या संगठन को निशाना नहीं बनाता और दूसरे क्षेत्रीय देशों के लिए भी खुला है। लेकिन



अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दस्तावेज की भाषा नहीं देखी जाती, टाइमिंग भी देखी जाती है। और इस समझौते की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है क्योंकि इस समय ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर है। ईरान समर्थित हूती, इराकी मिलिशिया और अन्य समूहों की गतिविधियों ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ाई है। दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदल दिया है। इसलिए यह समझौता भले ही ईरान का नाम न ले, लेकिन ईरान के लिए इसका संदेश साफ है कि सऊदी अरब अब अकेला नहीं है। राजनीति

ईरान की बढ़ेगी मुश्किलें – वहीं इस समझौते के बाद ईरान के लिए नई चुनौती खड़ी हो गयी है। तेहरान अब तक पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव का बड़ा हिस्सा सहयोगी और प्रॉक्सी संगठनों के नेटवर्क के जरिए कायम करता रहा है। लेकिन यदि सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और तुर्किये की रक्षा तकनीक का समर्थन मिलने लगे तो क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि मक्का समझौते को ईरान के खिलाफ सीधा सैन्य गठबंधन नहीं होते हुए भी ईरान के लिए रणनीतिक चुनौती जरूर माना जा सकता है।

इजराइल-अमेरिका को भी संदेश – दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन का एक और बड़ा संदेश इजरायल के लिए भी है। पश्चिम एशिया में जिस ‘सुन्नी धुरी’ की चर्चा लंबे समय से होती रही है, वह अब सिर्फ राजनीतिक अवधारणा नहीं रहना चाहती। साथ ही यह अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है और यह समझौता वाशिंगटन के लिए भी सुखद खबर नहीं है। दरअसल सऊदी अरब और तुर्किये दोनों अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के पुराने साझेदार हैं। लेकिन यदि यही देश अपनी सुरक्षा के लिए अलग क्षेत्रीय सैन्य ढांचा बनाने लगे तो इसका अर्थ साफ है कि अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर भरोसा कम हो रहा है। यही इस समझौते का सबसे बड़ा दीर्घकालिक रणनीतिक अर्थ हो सकता है।

सुन्नी नाटो सिर्फ कल्पना है या हकीकत? – इसके अलावा, यदि मक्का मॉडल सफल होता है और उसमें दूसरे सुन्नी देश शामिल होते हैं, तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था के समानांतर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा खड़ा हो सकता है। सवाल उठता है कि इसमें और कौन-से देश शामिल हो सकते हैं? इसके जवाब में कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया जैसे देशों के नाम संभावित सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि यूएई की कई क्षेत्रीय मुद्दों पर सऊदी अरब और तुर्किये से अलग नीति रही है। साथ ही मिस्र भी किसी ऐसे सैन्य गठबंधन में फंसना नहीं चाहेगा जो उसे सीधे

किसी क्षेत्रीय युद्ध में धकेल दे। वहीं सीरिया अपनी युद्धोत्तर परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ‘सुन्नी नाटो’ का विस्तार संभव जरूर है, लेकिन आसान नहीं है।

त्रि-पक्षीय समझौते का भारत पर क्या होगा असर ? – अब सवाल यह है कि इस रक्षा समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा और अगर भारत-पाकिस्तान के बीच फिर सैन्य टकराव हुआ तो क्या तुर्किये और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? देखा जाये तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक क्षमता है। तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान का करीबी सैन्य साझेदार है और कश्मीर से लेकर रक्षा सहयोग तक उसका रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव में भी अंकारा ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान को तुर्किये से ड्रोन, हथियार, तकनीक, खुफिया सहयोग और सैन्य सहायता का अधिक संगठित समर्थन मिल सकता है। हालांकि सऊदी अरब को तुर्किये के साथ एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा क्योंकि रियाद के पाकिस्तान से गहरे रक्षा संबंध जरूर हैं, लेकिन भारत तो उसके लिए ऊर्जा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग का अहम साझेदार है। इसलिए भारत-पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में तुर्किये का पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़ा होना ज्यादा संभावित है, जबकि सऊदी अरब के लिए सीधे भारत के खिलाफ युद्ध में उतरना आसान नहीं होगा। वह पाकिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक या सीमित सैन्य-लॉजिस्टिक मदद दे सकता है, लेकिन मक्का समझौते की मौजूदा सार्वजनिक भाषा से यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में सऊदी और तुर्किये अपने आप भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। यही वजह है कि भारत के लिए असली चिंता इस समझौते की ‘सामूहिक युद्ध’ वाली भाषा से ज्यादा पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अतिरिक्त सैन्य और रणनीतिक ताकत है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

पाकिस्तान का विरोधाभास – हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोधाभास भी सबके सामने आया है। जिस देश की अपनी सीमाओं पर लगातार तनाव है, जिसे अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बलूचिस्तान प्रांत ने आजादी का ऐलान कर दिया है, जिसके अवैध कब्जे वाले पीओके में विद्रोह और दमन तेज होता जा रहा है, वह देश अब मुस्लिम दुनिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रहरी बनने की भूमिका तलाश रहा है।

हिमालयी नदियों में बढ़ रहा खतरा, बदलते जलवायु संकट से पहाड़ से मैदान तक मंडरा रही बाढ़ की आशंका

(जयप्रकाश त्रिपाठी)

वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति भी बढ़ रही है। जलवायु आपदा के कारण हिमालयी नदियां खतरनाक रूप से अपने प्रवाह के रास्ते बदल रही हैं। यह खतरे की घंटी है। उधर, आर्कटिक क्षेत्र, पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इस क्षेत्र में जमे हुए पानी की मात्रा में गिरावट जारी रहना और बैरेंट्स सागर, बेरिंग सागर तथा ओखोत्स्क सागर में जमे हुए जल की क्षति गंभीर बदलाव का संकेत है। इससे सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करने की आर्कटिक क्षेत्र की क्षमता में कमी आती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र, मौसमी रझान और ध्रुवीय क्षेत्रों में आजीविका भी प्रभावित हो सकती है।

‘चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेज और सिचुआन यूनिवर्सिटी’ के वैज्ञानिकों के मुताबिक वैश्विक ताप के कारण होने वाले मौसमी बदलावों से ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में नदियां और उनके किनारे बसे इलाकों के लिए गंभीर खतरा पड़ने हो गया है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता इत्यादि नदियों से लगभग 19 नदियां सीधे जुड़ी हैं, जिनके तेज प्रवाह से जन-धन का व्यापक नुकसान हो सकता है। पहले के मुकाबले दोगुनी तेज गति से ये नदियां, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे तबाह कर सकती हैं। हिमालयी नदियों के 1582 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में तापमान की संवेदनशीलता वैश्विक औसत से लगभग आठ गुना ज्यादा है। नदियों की ही तरह इन क्षेत्रों का तापमान भी दोगुनी गति से बढ़ रहा है। नदियों की गति में बदलाव का सीधा संबंध जलवायु आपदा, तापमान और हिमनदों की हलचल से है।

जलवायु आपदा से अर्थव्यवस्थाएं तहस-नहस हो रही हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे बदलाव आ सकते हैं, जिन्हें पलटना असंभव होगा। शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति भी बढ़ रही है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत तापमान वृद्धि की सीमा अहम है।

हिमालय के आर-पार इस आपदा से बहुत बड़ी आबादी गंभीर रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है। ताजा अध्ययन के मुताबिक खास तौर से अरुणाचल प्रदेश की नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह भयावह हो सकता है। असम पहले से ही ऐसी आपदाएं झेल रहा है।

जलवायु आपदा से अर्थव्यवस्थाएं तहस-नहस हो रही हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे बदलाव आ सकते हैं, जिन्हें पलटना असंभव होगा। शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं कि वर्ष 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। मौसम विज्ञानियों का विश्लेषण बताता है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की गति तेज हो रही है और अत्यधिक गर्मी की आवृत्ति भी बढ़ रही है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत तापमान वृद्धि की सीमा अहम है। ऐसी स्थिति में चरम मौसमी घटनाओं, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्र ढहने का जोखिम बढ़ेगा। गर्म हो रही जलवायु से वैश्विक वर्षा रझानों में भी बदलाव नजर आ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि दुनिया भीषण गर्मी की ओर बढ़ रही है। यह लगभग तय है कि अगले पांच

वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर या फिर उसके आसपास बना रहेगा। ब्रिटेन के मौसम विज्ञान विभाग ने इस रिपोर्ट में पिछले पांच वर्षों की जलवायु का आकलन और अगले पांच वर्षों में तापमान, बारिश और बर्फबारी के रझानों में आकांक्षित किया है। वर्ष 2026 से 2030 के दौरान, इस बात की लगभग 86 फीसद आशंका है कि कम से कम एक वर्ष, रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक गर्म वर्ष होने का मामला सामने आए। अगले पांच वर्ष की अवधि में, कम से कम एक वर्ष के दौरान औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

बीती जुलाई में, हिमालयी क्षेत्रों से लेकर अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ग्रामीण इलाकों तक आई भीषण बाढ़ की घटनाओं में कई लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच, समय-पूर्व चेतावनी प्रणालियों की गंभीर खामियां भी उजागर हुईं हैं। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस विनाश के पीछे तेजी से हो रहा शहरीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन जैसी वजहें हैं, जिनसे वातावरण में नमी बढ़ रही है और बाढ़ का खतरा भी लगातार गहराता जा रहा है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अतिरिक्त एक डिग्री

सेल्सियस तापमान बढ़ने पर, वायुमंडल लगभग सात फीसद अधिक जलवाष्प अपने भीतर संचित कर सकता है। इस स्थिति से अत्यधिक वर्षा का जोखिम बढ़ रहा है। साथ ही गर्म होती जलवायु के कारण तेजी से पिघलती बर्फ से हिमनद से जुड़ी बाढ़ का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अकेले बीती जुलाई में ही दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक के बाद एक, बाढ़ की घटनाएं देखी गईं। कहीं भारी बारिश, कहीं हिमनद झीलों का विस्फोट और कहीं अचानक आई बाढ़ का कहर टूटा है।

वर्ष 2020 में, दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में भीषण बाढ़ की घटनाओं में साढ़े छह हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी और लगभग 105 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति दर्ज की गई थी। दो साल बाद 2022 में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस साल भी यह सिलसिला थमा नहीं है। दक्षिण कोरिया में 16 से 20 जुलाई के बीच रिकॉर्डतोड़ बारिश दर्ज की गई, जहां कुछ इलाकों में वर्षा 115 मिलीमीटर प्रति घंटे से भी अधिक पहुंच गई। इस आपदा में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 13 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।

बीती जुलाई में अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने टेक्सास के पहाड़ी क्षेत्र में तबाही मचा दी, जिसमें सी से अधिक लोगों की जान चली गई और अनेक लोग लापता हो गए। इसी तरह नेपाल के रसुवा जिले में हिमनद की सतह पर बनी झील के फटने से अचानक आई बाढ़ में कुछ जलविद्युत संयंत्र और एक पुल सहित कई सड़कें बह गईं। इस भीषण घटना में कम से कम 11 लोगों की जान गई। अनेक लोग अब भी लापता हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में बाढ़ अब पहली बार की तुलना में अधिक बार आ रही है, जबकि दो दशक पहले ऐसी बाढ़ आम तौर पर हर पांच से दस साल में एक बार आती थी। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि भविष्य में बाढ़ की ऐसी घटनाओं का खतरा तीन गुना तक बढ़ सकता है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 1.81 अरब लोग यानी दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी विनाशकारी बाढ़ की जद में है। इस आबादी में से 89 फीसद लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों के हैं।

भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई है। पंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से जन-जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। नगालैंड में बारिश के बाद भूस्खलन से स्कूल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से लगभग कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल में भी इन दिनों 36 सड़कें बंद हैं। असम के बारह जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।

